



खुद को ब्रह्मा, विष्णु, महेश
और राम कहने वाले बाबाओं
पर महाकुंभ में लगेगा बैन,

112 को नोटिस जारी

नई दिली, 17 जुलाई भारत में
खुद को भगवान कहने वाले बाबाओं की
तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे
बाबाओं पर अखाडा परिषद के अध्यक्ष
रविंद्र पुरी महाराज ने नाराजी जाहिर
की है तिन अखाडों ने आगे 112 संतों
को नोटिस दिया है।

अखाडा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र

पुरी महाराज ने कहा कि आजकल ऐसा

ट्रॉड चला है कि हर कोई अपने आप को

उपासक-पुजारी नहीं, भगवान कह रहा

है। खुद को ब्रह्मा,

विष्णु, महेश और राम

कह रहे हैं, ऐसे संतों पर कारबाही होना

अति अवश्यक है। प्रयागराज के कुम्ह में

ऐसे विद्युतों को भूमि नहीं दी जाएगी

जिसको लेकर 112 संतों को नोटिस भी

जारी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने

कहा कि हमारी सनातन संस्कृति के विरोध

में जो जाएगा, उस पर करवाई होगी। मध्य

से अलाह हूँ अकबर कहना, नामाज जुना

उचित नहीं है। मध्य पर पति-पत्नी बैठतर

शादी करें, ये जीं अच्छी नहीं हैं। ऐसे

संतों को विद्युत विजया जाएगा, जो सनातन

के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बता दें कि जाना

अखाडे ने 54 संत, श्री निरंजनी अखाडे

ने 24 संतों और निर्मांही अनी अखाडे ने

34 संतों को नोटिस थामया है। संतों ने

30 सितंबर तक संतोषजनक जवाब नहीं

दिया तो महाकुंभ-2025 में प्रवेश नहीं

मिलेगा। अखाडे सनातन धर्मविद्यों की

आस्था व समर्पण का केंद्र है। मैं जूदा

समय 13 अखाडे हैं। उन्हें अधिकल

भारतीय अखाडा परिषद के माध्यम से

संगति किया गया है।

आर्यसमाज सम्मेलन 21 को

पिलियामंडी, 17 जुलाई गुरु

एक्सप्रेस। आर्यसमाज का सम्मेलन 21

जुलाई को प्रातः 11 बजे रत्नाल मेले

कॉलोनी में होगा। आर्यसमाज सम्भाग

प्रधान बंसीलाल आर्य (बर्खेडांपंथ) ने

यह जानकारी दी।

मंदसौर, 17 जुलाई गुरु

एक्सप्रेस। मंदसौर सहित अन्य राजस्व

से जुड़े लंबित मामलों के तोड़ी के साथ

निराकरण के लिए पटवारी और राजस्व

निरीक्षक संविदा पर रखे जाएंगे। इसमें

सेवानिवृत्त पटवारी और राजस्व

निरीक्षक को अवश्यक

करने के लिए जाएंगे।

झोन रे होगा सर्व-प्रदेश में 18

जुलाई से फिर राजस्व महाभियान प्रारंभ

किया जा रहा है। इसमें नामांतरण,

बंटवारा, सीमांकन के लंबित मामलों का

निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा,

साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान

निराकरण के लिए जाएगा।

लंबित नामांतरण प्रकरणों (विवादित/अविवादित) का निराकरण

एवं उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को भी दर्ज किया जाएगा।

30 जून, 2024 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लम्बित

प्रकरणों को चिह्नित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के

प्रकरणों का निराकरण।

लंबित नामांतरण प्रकरणों (विवादित/अविवादित) का निराकरण

एवं उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को भी दर्ज कर निराकरण।

लंबित बंटवारा प्रकरणों का निराकरण एवं 06 माह की अवधि के

लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धीकरण के प्रकरणों का

निराकरण।

खसरे में बटांकन होना परंतु नवशे में बटांकन नहीं होने के प्रकरणों

में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार।

खसरा नंबर का एक से अधिक बार होने के प्रकरणों का पटवारी

एवं तहसीलदार द्वारा निराकरण।

भू-अभिलेखों का शुद्धीकरण

लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण

दिजिटल क्रॉप सर्व

नवशे में बटांकन होना एवं खसरे में नहीं होना ऐसे मामलों का भूलेख

पोर्टल पर बहुल नवशा बटांकन (Village Map Correction) मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा निराकरण।

समग्र वेब पोर्टल, MPONLINE/CSC कियोस्क के माध्यम से

समग्र में आधार की e-KYC करने की सुविधा नागरिकों को

निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

पीएम किसान योजना से छूटे हुए पात्र किसानों को योजना में जोड़ा जायेगा एवं अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएमकिसान पोर्टल पर अद्यतन की जायेगी।

स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर अधिकार अभिलेख का वितरण समारोहपूर्वक सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रत्येक किसान की फार्म आईडी तैयार की जायेगी।

खरीफ-24 में डिजिटल क्रॉप सर्व किया जायेगा।

पटवारी डायरी का मैनुअल के स्थान पर डिजिटल संधारण किया जायेगा, जिसमें वास्तविक लोकेशन पर उपस्थिति दर्ज होने से कार्य पारदर्शिता से होंगे।

30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण लक्षित

लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण

दिजिटल क्रॉप सर्व

नवशे में बटांकन होना एवं खसरे में नहीं होना ऐसे मामलों का भूलेख

पोर्टल पर बहुल नवशा बटांकन (Village Map Correction) मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा निराकरण।

समग्र वेब पोर्टल, MPONLINE/CSC कियोस्क के माध्यम से

समग्र में आधार की e-KYC करने की सुविधा नागरिकों को

निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

पीएम किसान योजना से छूटे हुए पात्र किसानों को योजना में जोड़ा जायेगा एवं अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएमकिसान पोर्टल पर अद्यतन की जायेगी।

स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर अधिकार अभिलेख का वितरण समारोहपूर्वक सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रत्येक किसान की फार्म आईडी तैयार की जायेगी।

खरीफ-24 में डिजिटल क्रॉप सर्व किया जायेगा।

पटवारी डायरी का मैनुअल के स्थान पर डिजिटल संधारण किया जायेगा, जिसमें वास्तविक लोकेशन पर उपस्थिति दर्ज होने से कार्य पारदर्शिता से होंगे।

भू-अभिलेखों का शुद्धीकरण

लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण

दिजिटल क्रॉप सर्व

नवशे में बटांकन होना एवं खसरे में नहीं होना ऐसे मामलों का भूलेख

पोर्टल पर बहुल नवशा बटांकन (Village Map Correction) मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा निराकरण।

समग्र वेब पोर्टल, MPONLINE/CSC कियोस्क के माध्यम से

समग्र में आधार की e-KYC करने की सुविधा नागरिकों को

निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

पीएम किसान योजना स